

संवहनीय विकास एवं नवोन्मेष का संचालन



मजबूत जीडीपी वृद्धि और सशक्त नीतिगत सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर समृद्धि के लिए "स्वीट स्पॉट" में पहुंचा दिया है.

श्रीनिवासन वरदराजन
अध्यक्ष



प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2023-24 (वि. व. 24) के लिए हमारी 105वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट बैंक के वित्तीय आंकड़ों के साथ-साथ हमारे सामाजिक, पर्यावरणीय और गवर्नेंस पहलों की जानकारी भी प्रदान करती है। इस प्रकार, यह हमारे वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र, समाज और पर्यावरण में हमारे योगदान की समग्र छवि प्रस्तुत करती है। यह वर्ष यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक यादगार वर्ष रहा है। हम अधिक सशक्त और मजबूत हुए, और यह केवल हमारे कारोबार के आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि हमारे ग्राहकों द्वारा हम पर व्यक्त किए गए विश्वास में भी परिलक्षित होता है। मैं हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों का हमारे बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनके अटूट

सहयोग और परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका निरंतर विश्वास हमें जिम्मेदार बैंकिंग और समावेशी विकास की दिशा की ओर प्रेरित करता है।

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, भारत का आर्थिक निष्पादन वैश्विक चुनौतियों और भू-राजनीतिक चिंताओं के बावजूद मजबूत बना रहा। वित्तीय वर्ष 24 में लगभग 8% की मजबूत जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई और वित्तीय वर्ष 25 के लिए 7.0% की वृद्धि का पूर्वानुमान है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों ने समष्टि स्थिरता में सहयोग किया है। सरकार की पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि ने विकास में सहयोग किया है और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित किया है। अगले वर्ष भी पूंजीगत व्यय पर जोर

देने की उम्मीद है ताकि विकास की पुनर्प्राप्ति सही दिशा में बनी रहे। हाल की तिमाही के क्षमता उपयोग के रुझानों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और यह निजी कैपेक्स चक्र को प्रोत्साहित करने में बल प्रदान करेगा। वित्तीय वर्ष 24 में मुद्रास्फीति 5.4% रही और वित्तीय वर्ष 25 में इसके 4.5% तक घटने की उम्मीद है। आर्थिक विकास की मजबूत प्रवृत्तियों और घटती मुद्रास्फीति के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में "स्वीट स्पॉट" में है।

बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन उल्लेखनीय रहा है जिसमें लाभ में वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार और तुलन पत्र प्रबंधन शामिल है। निरंतर ऋण वृद्धि, डिजिटल को अपनाने में बढ़ोत्तरी और सहायक सरकारी नीतियाँ क्षेत्र को पुनः सक्रिय करने में सहायक रही हैं। दिवाला और

दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों ने बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट को मजबूत किया है। इससे बैंकिंग क्षेत्र के सुदृढ़ता संकेतकों में सुधार हुआ है। बैंक पर्याप्त पूंजीकृत बने हुए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बाजार मूल्यांकन में बढ़त हुई है। मजबूत बैलेंस शीट के साथ पर्याप्त पूंजी और तरलता बफर बैंकों को भविष्य के झटकों का सामना करने की क्षमता देते हैं। वित्तीय वर्ष 24 में भारत में ऋण वृद्धि दो अंकों में बनी रही और जमा से महत्वपूर्ण अंतर से आगे निकल गई। आगामी समय में स्थिर ब्याज दरें, मजबूत जीडीपी, घटती मुद्रास्फीति और विकासोन्मुखी एवं बुनियादी ढांचा खर्च पर सरकार का ध्यान बैंकिंग क्षेत्र के मजबूत विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

यह कहते हुए कि, भले ही बैंकों का तुलन पत्र मजबूत है, उन्हें अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत और सक्रिय बने रहना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान एक मजबूत और सतत ऋण चक्र सुनिश्चित करने पर है जिसमें नीति का फोकस गवर्नेंस, समझदारी और तकनीक इन तीन प्रमुख मानकों पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण अत्यधिकता को नियंत्रित करने और उच्च वृद्धि वाले ऋण उत्पादों से जुड़े जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से समष्टि विवेकपूर्ण मानदंडों को प्रस्तुत करने में सक्रिय रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तुलन पत्र के देनदारी पक्ष पर भी ध्यान केंद्रित किया है जिससे ऋण जमा अनुपात मेट्रिक को बैंकों की समग्र वृद्धि को कैलिब्रेट करने में एक प्रमुख कारक बनाया गया है।

गवर्नेंस एक सदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आधारशिला है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल रही एकचर्चाओं और परामर्शों के माध्यम से आश्वासन कार्यों की महत्वपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया है। बैंक के बोर्ड और प्रबंधन ने जोखिम, लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित संसाधनों एवं अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से उच्च प्राथमिकता दी है। इस वर्ष की कार्यनीति बैठक का विषय आश्वासन कार्यों को बढ़ाने और उन्नत करने पर

केंद्रित था। आगे की राह पर विचार-विमर्श करने के अलावा, स्वतंत्र गवर्नेंस विशेषज्ञों ने गवर्नेंस के सही रुख और दृष्टिकोण पर भी सुझाव दिए।

डिजिटलीकरण में बढ़ोतरी के साथ वित्तीय क्षेत्र में तकनीक एक प्रमुख बिंदु बन गया है। जैसे-जैसे बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएँ तकनीक के लाभों का उपयोग कर रही हैं, भारतीय रिजर्व बैंक तकनीक के उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों जैसे डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और तकनीक-प्रेरित धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वित्तीय संस्थानों के खिलाफ साइबर सुरक्षा हमलों के बढ़ते रहने के साथ, बैंकों और अन्य वित्तीय संगठनों को अपनी और अपने डेटा की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए। साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने और आघात सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग, स्वचालन और अधिक सुरक्षित क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए मानकीकृत नियंत्रण आवश्यक है। आपके बैंक के बोर्ड ने तकनीकी ढांचे में निवेश को बढ़ाया है और बेहतर ग्राहक सहभागिता और सेवा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।

जबकि समग्र बैंकिंग व्यवस्था एक अच्छी स्थिति में है, हम जोखिमों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुख्य जोखिमों में कम लागत वाली जमाराशियां जैसे कासा जुटाने में बढ़ती कठिनाई शामिल है। खुदरा ग्राहक जमाराशि जुटाने के लिए समग्र माहौल भी बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है और यह आगामी वर्ष में बैंक के निष्पादन को निर्धारित करने वाला एक संभावित महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। अन्य जोखिम चुनाव पश्चात के परिदृश्य में निजी कैपेक्स की पुनर्प्राप्ति वर्तमान अपेक्षानुसार व्यापक रूप में नहीं हो पाने की संभावना है। एनबीएफसी ने खुदरा ऋण देने में सक्रिय भूमिका निभाई है और जैसे-जैसे उनके लिए तरलता कम होती जाती है, उनके परिसंपत्ति पोर्टफोलियो पर इसके आगामी प्रभाव को देखना महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि व्यापक पोर्टफोलियो स्तर पर परिसंपत्ति गुणवत्ता में किसी बड़े दबाव के संकेत नहीं थे, उपर्युक्त खंडों में लगातार उच्च ऋण वृद्धि के कारण नियामक द्वारा चेतावनी और हस्तक्षेप अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष 24 में, यूनियन बैंक ने अपने प्रभावशाली कार्यनिष्पादन को जारी रखा है। बैंक ने ग्राहक सुविधा के लिए विभिन्न डिजिटल और डिजिटल रूप से सहायता प्राप्त यात्राओं को सक्षम करने, होम शाखाओं से इतर शाखाओं पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संख्या बढ़ाने, ग्राहक शिकायतों के लिए एकीकृत शिकायत प्रबंधन उपाय के माध्यम से ग्राहक सेवा, खतरे को कम करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा, अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन संचालन का अनुकूलन, विश्लेषिकी-आधारित दबाव परीक्षण मॉडल को अपनाने, लक्ष्य निर्धारण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और डिजिटल जनबल आयोजना और पदस्थी में अच्छी प्रगति की है। बैंक कासा और खुदरा ग्राहक जमाराशि की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसका उपयोग अपने विभिन्न खंडों में ऋण वृद्धि को कैलिब्रेट करने के लिए करेगा। अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और हम सही हामीदारी अंकन प्रथाओं और सतत ऋण पिकअप सुनिश्चित करने के भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। चूकि क्रेडिट को बढ़ने में एक दशक लगता है, अतः यह एक प्रमुख ध्यान देने योग्य क्षेत्र है। वित्तीय वर्ष 24 में बैंक द्वारा पूर्ण पूंजी जुटाव कार्य बैंक को एक सुदृढ़ पूंजी स्थिति प्रदान करता है जिसका उपयोग भारत के विकास की गति को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए किया जा सकता है।

हमें आशा है कि विभिन्न हितधारक यूनियन बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन की सराहना करेंगे और आने वाले वर्षों में उन्हें इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। हम ग्राहक मूल्य बढ़ाने, तकनीकी प्रगति को अपनाने, और हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध और अग्रसर हैं।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

श्रीनिवासन वरदराजन
अध्यक्ष